Import of Wheat

609. KUMARI ALIA :
SHRI KAMAL MORARKA:
SHRI M.S. GURUPADA-SWAMY :

Will the Minister of FOOD be pleased to stats:

(a) whether Government have taken a decision to import wheat ;

(b) if so, the quantity and value of wheat to be imported;

(c) the reason for import of wheat inspite of bumper crop and comfortable buffer stock position;

(d) the details of month-wise supply and off-take of wheat from PDS;

(e) the implications on the food subsidy;

(f) whether it is a fact that wheat is being exported ; and

(g) if so, the quantity and rate thereof and the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOl): (a) to (c) The Government have recently deicided to import one million tonnes of wheat with a view to increase its availability and to contain market prices. Value of the wheat to be imported will be known after finalisation of contracts.

(d) A statement is attached. (*See* below).

(e) The extent of subsidy involved in the issue of imported wheat through the Public Distribution System will depend on the landed cost of wheat.

(f) and (g) As a part of emergency measures to generate foreign exchange earnings to cope with the critical balance of payments situation, the Government decided to export wheat. During 1991-92, 6-52 lakh tonnes of wheat have been exerted by ST.G./M.M.T.C. upto 15 February, 1992 on commercial basis at prices ranging from US £ 92 to US £ 109 per MT FOB.

Statement

Allotment and off-take of wheat for the public distribution system from the central pool during January to December, 1991

(In lakh tonnes)

Month	Allotment	Off-Take
January . . .	8.48	7.92
February	9.57	8.07
March	9.99	8.44
April	10.49	6.98
May	10.68	6.80
June .	7.74	6.26
July	7.86	7.63
August	8.00	7.18
September	8.10	7.68
October...	8.65	7.83
November	8.68	7.01
December.....	7.83	7.27
	106.07	89.07

खाद्यान्न स्टाक का पता लगाया जाना

610. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह महीनों तथा इस महीने के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा मारे गए छापों के माध्यम से दोनों ने कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के खाद्यान्न स्टाक का पता लगाया है; और

(ख) इस अवधि के दौरान दायर की गई प्रथम सूचना रिपोर्टों और गिरफ्तार किए गए कालाबाजारियों और जमाखोरों की संख्या कितनी है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

गेहूं का आयात

511. **श्री धूलेश्वर मीणा** :
श्री राम जेठमलानी :
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि सरकार ने देश में खाद्यान्नों की कमी देखते हुए और उनकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए 10 लाख टन खाद्यान्न आयात करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने आयात की व्यवस्था करने के लिए उच्च अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजा था ;

(ग) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल में सम्मिलित अधिकारियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं तथा क्या इन अधिकारियों को खाद्यान्न आयात करने का पूर्व अनुभव था और यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार इस वर्ष भी गेहूं आयात करने का विचार रखती है; यदि हां, तो उस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या यह सच है कि देश में आयात और निर्यात मुख्यतः खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जाता है और यदि हां, तो इन दो अभिकरणों के माध्यम से खाद्यान्न का आयात न कराए जाने के क्या कारण हैं ; और

(च) सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने किन-किन देशों का दौरा किया तथा वहां पर कितने-कितने दिन बिताए तथा इस दौरे पर अनुमानतः कितना खर्चा आया ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई): (क) सरकार ने हाल ही में गेहूं की उपलब्धता में वृद्धि करने और बाजार मूल्यों को नियंत्रित रखने की दृष्टि में एक मिलियन मीटरी टन गेहूं का आयात करने का निर्णय किया है।

(ख) (ग) और (च) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है (नीचे देखिए)।

(घ) गेहूं का आयात करने के निर्णय की दृष्टि में, खनिज तथा धातु व्यापार निगम/राज्य व्यापार निगम द्वारा पहले से किए गए ठेकों की शर्तों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वर्ष में गेहूं के निर्यात को यथा सम्भव प्रतिबन्ध रखने का निर्णय किया गया है।

(ङ) खाद्य मंत्रालय की नीति के अनुसार, आयात और निर्यात नीति (अप्रैल, 1990–मार्च, 1993) के आधार पर अनाजों का आयात केवल भारतीय खाद्य निगम द्वारा ही किया जाएगा।

विवरण

गेहूं का आयात करने के लिए भेजे गए प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों, विभिन्न देशों में उनके ठहरने और अनुमानित खर्च के बारे में सूचना

अधिकारी का नाम	पदनाम	जितने दिन निम्न देशों में ठहरे, उनकी संख्या			अनुमानित खर्च (होटल प्रभारों को छोड़कर)
		बैल्जियम	कनाडा	संयुक्त राज्य अमेरिका	
खाद्य मंत्रालय :					
श्री पी० त्रिपाठी	सचिव	3	2	12	3.51 लाख रुपये
श्री एम० सीताराम	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार	3	2	27	
डा० जी० के० गिरीश	संयुक्त आयुक्त (भंडारण तथा अनुसंधान)	3	2	12	
जल यातायात परिवहन मंत्रालय :					
श्री एन० पी० चौहान	चार्टरिंग अधिकारी	–	–	12	रु० 86,200

ऐसे प्रतिनिधि मंडलों में अधिकारियों को शामिल करने के लिए पिछला अनुभव एक मानदंड नहीं है। सामान्यतया, विषय से संबंधित अधिकारियों को भेजा जाता है।

Subsidised wheat to flour mills

612. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL :Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Govern ment are exporting 10 lakh tonnes of wheat at lower rates and importing 1 million tonne of wheat on high price;

(b) if so, the justification therefor ;

(c) whether it is also a fact that Government have provided 15 lakh tonnes of wheat to big flour mills in the country at subsidised rates without maintaining any price control;

(d) whether the mill owners are earning cent-per cent profit on the wheat supplies received by them ; and

(e) whether Government propose to inquiie into the matter, if so, by when and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI TARUN GOGOI) : (a) and (b) As a part of emergency measures to generate foreign exchange earnings to cope with the critical balance of payment situation, the Government had decided to export wheat. During 1991-92, a quantity of 6-52 lakh tonnes of wheat has been exported upto 15th February, 1992 by STC/ MMTC on commercial basis at prices ranging from US £ 92 to *VS* 109 per M.T. FOB. The Government have recently decided to import one million tonnes of wheat with a view to improve its availability and to contain